

खुद को मजबूत बनाओं जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी।

- अज्ञात

हम कोई इकलौती अर्थव्यवस्था नहीं

हालांकि मामला इतना आसान भी नहीं है। ध्यान रखना होगा कि इस दौरान यानी अप्रैल से जून की अवधि में प्राइवेट फाइनेल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (पीएफसीई) के आंकड़े 54.3 फीसदी गिर गए जबकि पिछले साल की इसी अवधि में इसमें 56.4 फीसदी की बढ़त हुई थी।

राम अवतार सिंह।।

सोमवार को जारी मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों ने किसी खुशफहमी के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी है। सबको पता था कि आंकड़े गिरावट वाले होंगे लेकिन गिरावट 23.9 फीसदी की हो जाएगी, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। निश्चित रूप से ये आंकड़े गंभीर हैं, लेकिन जीडीपी में गिरावट का गवाह बनने वाले हम कोई इकलौती अर्थव्यवस्था नहीं हैं। कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन लगभग सारे देश विकास दर में अच्छी-खासी गिरावट का सामना कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि खराब आंकड़ों के पीछे सीधे तौर पर यह वजह काम कर रही है कि इस तिमाही के दौरान 68 दिन से भी ज्यादा समय तक देशव्यापी लॉकडाउन लागू रहा, जिसमें तमाम आर्थिक

गतिविधियां करीब-करीब ठप हो गई थीं। अकेला कृषि क्षेत्र इससे मुक्त रहा। नतीजा यह कि जहां तमाम सेक्टर गिरावट दिखा रहे हैं वहीं कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तिमाही इसमें 3.4 फीसदी की वृद्धि हुई जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई थी।

सवाल है कि अकेले कृषि क्षेत्र की बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था को कितना सहारा दे पाएगी। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि इस भीषण गिरावट से उबरने की क्या सूत्र हो सकती है। इन दोनों सवालों का जवाब खोजने के सूत्र हमें इस एक तथ्य में मिलते हैं कि इस गिरावट को विशुद्ध आर्थिक परिघटना नहीं माना जा सकता। इसके पीछे लॉकडाउन का वह फंसला है जो कोरोना वायरस से बचाव को ध्यान में

रखते हुए लिया गया था। इस आपदा का तात्कालिक और अस्थायी चरित्र हमारी उम्मीद का सबसे बड़ा आधार है। कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे लॉकडाउन की बंधिशें हटेंगी वैसे-वैसे अर्थव्यवस्था की सेहत दुरुस्त होती जाएगी। हालांकि मामला इतना आसान भी नहीं है। ध्यान रखना होगा कि इस दौरान यानी अप्रैल से जून की अवधि में प्राइवेट फाइनेल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (पीएफसीई) के आंकड़े 54.3 फीसदी गिर गए जबकि पिछले साल की इसी अवधि में इसमें 56.4 फीसदी की बढ़त हुई थी।

पीएफसीई परिवारों की खपत आंकने का सटीक पैमाना माना जाता है। लॉकडाउन ने अगर उनके कार या टीवी खरीदने के फैसले को प्रभावित किया है तो इसकी वजह सिर्फ मौजूदा संकट नहीं

है। किसी भी परिवार में ऐसे फैसले भविष्य की निश्चितता या अनिश्चितता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। यानी जरूरत सिर्फ यह नहीं है कि जिन भी क्षेत्रों को खोला जा सकता है उन्हें जल्द से जल्द खोला जाए। जरूरत यह भी है कि मजदूरों-कर्मचारियों के काम और उनके वेतन की गारंटी की जाए और उनमें यह भरोसा कायम किया जाए कि उनकी नौकरी आगे भी बची रहेगी। ज्यादातर दफतरों-कारखानों को बंद होने से रोका जा सका तो बाजार का संकुचन ज्यादा नहीं खिंचेगा और भारत लंबी मंदी का शिकार होने से बच जाएगा। जाहिर है, देश के सामने संकट बहुत बड़ा है, लेकिन एक अच्छी बात भी है कि सुरंग के दूसरे छोर से रोशनी की किरणें दिखनी बंद नहीं हुई हैं।

निष्ठा

अशोक बोहरा।
निष्ठावान बनने।
निष्ठा यानी विश्वास। यह एक ऐसी भावना है, जो हमें खुशियां प्रदान करती है। यह एक सकारात्मक भावना है। सच्ची खुशी पाने के लिए सकारात्मक सोच होना बहुत जरूरी है और यह सोच हमें निष्ठा और विश्वास के साथ मिलती है। जो लोग अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के प्रति शक करते हैं या जिन लोगों को किसी पर भी विश्वास है वे सदा दुखी रहते हैं, क्योंकि अविश्वास की भावना रखने वालों के प्रति दूसरे लोग भी अविश्वास ही करते हैं। यात्रा से ढेर सारे अनुभव मिलते हैं और इसकी खुशी देर तक आपके दिमाग में रहती है। आपके अनुभव यादें बनकर आपके दिमाग में रहते हैं और जब भी आप इनके बारे में सोचते हैं, मूड एकदम रिफ्रेश हो जाता है। आपकी आंखों में झलका है विश्वास और अविश्वास।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

तुर्की की उलटी धार

भारत की धर्मनिरपेक्ष ताकतें आज उन हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ इसीलिए हैं क्योंकि आस्था के प्रश्न को इन्होंने केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है और न्यायपालिका तक इसमें विश्वास करती सी लगने लगी है। अभी हाल ही में तुर्की में पहले कभी चर्च और कभी मस्जिद, लेकिन 1934 से म्यूजियम के रूप में इस्तेमाल हो रही इमारत हाया सोफिया को वहां के राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक मस्जिद में बदलने की घोषणा की है और 10 जुलाई को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले पर मुहर लगा दी। इस फैसले का जश्न हमारे यहां इंडियन यूनिशन मुस्लिम लीग समेत कई मुस्लिम संगठनों ने मनाया। अगर आपकी मानसिकता ऐसी है तो फिर भला किस आत्मबल से आप बाबरी मस्जिद के ध्वंस और उसी जगह राममंदिर के निर्माण का विरोध कर सकते हैं? इसलिए आज मानव-अधिकार, लैंगिक समानता और न्याय के पक्ष में आवाज उठाने वाले धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें ही साधारण मुस्लिम जनता को यह बतलाना होगा कि 1500 वर्ष पहले लिखी गई कुरान की हर बात को जैसे का तैसा ग्रहण करना जरूरी नहीं है। केवल उन्हीं बातों पर अमल करें जिनका टकराव आज की स्थितियों से नहीं है और जो आज के समाज की जरूरत हैं। समय के साथ बदलने वाला नजरिया ही समाज को आगे बढ़ाता है। पाकिस्तान में जरूर कुछ 'नास्तिक' कहे जाने वाले संगठनों ने तुर्की के इस कदम की निंदा की है। भारत को धर्मनिरपेक्ष समाज बनाना है तो यह सोच बदलनी होगी।

पाकिस्तान बनने के बाद इन विशेषणों में यह भी जोड़ दिया गया कि मुसलमान 'देशद्रोही' होते हैं। इन गलतफहमियों का असर दंगों के रूप में दिखता है।

विश्व स्तर पर बढ़ती खाई

अजेय कुमार।।

भारत में जब इस्लाम का प्रवेश हुआ तो यहां के बाशिंदों के सामने पहली बार एक ऐसा धर्म प्रस्तुत हुआ जो समानता पर आधारित था। यही कारण रहा कि इसकी व्यापक अपील शूद्र और अति शूद्र जातियों के बीच देखी गई। इन उत्पीड़ित जातियों ने हिंदू धर्म के भेदभावपूर्ण व्यवहार से तंग आकर लाखों की संख्या में इस्लाम को कबूल किया। यहां के मठाधीशों और ब्राह्मणों ने इसका मुकाबला करने के लिए मुसलमानों को म्लेच्छ घोषित कर दिया। वक्त बीतने के साथ हिंदू सांप्रदायिक संगठनों द्वारा आम जनता में यह धारणा स्थापित की गई कि मुसलमान स्वभाव से ही हिंसक होते हैं, अपने घरों में चाकू, छुरे वगैरह रखते हैं, आदि-आदि। पाकिस्तान बनने के बाद इन विशेषणों में यह भी जोड़ दिया गया कि मुसलमान 'देशद्रोही' होते हैं। इन गलतफहमियों का असर दंगों के रूप में दिखता है।

अफसोस की बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी विशेषकर 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद से मुसलमानों के लिए खतरनाक बनी हुई हैं। तालिबान और अल-कायदा जैसे संगठन, जिन्हें पहले अमेरिका का वरदहस्त प्राप्त था और



जिन्हें अमेरिकी हुकूमत ने मुस्लिम बहुल देशों में धर्मनिरपेक्ष वाम-लोकतांत्रिक ताकतों को ध्वस्त करने में इस्तेमाल किया, आज मुसलमानों को फंडामेंटलिज्म की तरफ धकेलने में जुटे हुए हैं। इससे विश्व स्तर पर मुसलमानों और अन्य धर्मों के अनुयायियों के बीच खाई और बढ़ गई है। आज हमारे देश में मुसलमान सांसदों की संख्या महज 27 (5 फीसदी से भी कम) है और कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव सभाओं में मुस्लिम नेताओं को मंच पर बैठाने से परहेज करने लगी हैं। उन्हें डर है कि इससे कहीं हिंदू वोट नाराज न हो जाए। भारत के इतिहास में धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए इतनी विकट परिस्थितियां शायद पहले कभी नहीं थीं।

ऐसे में उम्मीद की जाती है कि जो इन हालात में सबसे अधिक त्रस्त हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभावपूर्ण व्यवहार झेलना पड़ता है, वे आगे आकर कुछ ऐसी पहल करें, जिससे उनकी

धूमिल होती छवि सुधरे और वे द्वेषपूर्ण प्रचार का मुहताब जवाब दे सकें। लेकिन दूसरों से धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक होने की मांग करने वाले मुस्लिम समाज को खुद भी इन मूल्यों पर खरा उतरना होगा। 1985 में उभरे शाहबानो मामले में मुसलमानों की छवि यह बनी कि वे शरीयत को भारत के संविधान और कानून से ऊपर मानते हैं और उसकी आड़ में तलाकशुदा बहियों को गुजारा भत्ता देने से बचना चाहते हैं। कौन भूल सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में उसके हक में फैसला दिया तो उस वर्ष देशभर में मुसलमानों ने प्रदर्शन किए और राजीव गांधी सरकार ने कठमुल्लों के सामने घुटने टेकते हुए 1986 में संसद से कानून पास करवा दिया जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करता था।

भारत में जिस किस्म के इस्लाम का चलन है, उसे वर्तमान सामाजिक-आर्थिक-भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करना होगा। मुसलमानों में यह माना जाता है कि देवदूत जिबरील के माध्यम से जो प्रवचन मोहम्मद साहब को सुनाए गए, वे सब अल्लाह के मुख से निकले थे और उन तमाम प्रवचनों का संग्रह कुरान में किया गया है। यानी अगर एक मुसलमान कुरान में लिखी किसी बात को दरकिनार करेगा तो वह सीधे अल्लाह से टक्कर लेगा। ऐसा महज सोचकर ही साधारण मुसलमान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

सूटोफु नवताल-5462				सूटोफु नवताल-5461 का हल			
2	9	5	4	7	8	1	6
4		2	7	8			
	1	6	8				3
8	5	9					7
3	6		2			1	9
1		3	5			2	
5		7	6	3			
	3	1	8			5	
9		6			2	1	

अपना ब्लॉग

एक गैर लोकतांत्रिक समाज ही होगा

मोहन। बाइबल में विश्वास करने वाले क्रिश्चियनों ने लगभग 500 वर्ष पहले ही इस व्यावहारिक जरूरत को स्वीकार कर लिया था। हिंदुओं के वेदों और पुराणों में कई बातें ऐसी लिखी हैं जो आज प्रासंगिक नहीं रह गई हैं और वे उन्हें सीरियसली नहीं लेते। यह अलग बात है कि जिन ताकतों ने आज समाज में सर उठा लिया है, वे पुष्पक विमान और गणेश जी की सर्जरी इत्यादि विषयों पर ज्ञान बांटते रहते हैं। संसद में कानून पास हो जाने के बावजूद 'तलाक, तलाक, तलाक' कह देने भर से एक मुस्लिम औरत घर के बाहर सड़क पर आ जाती है। क्या किसी ने सोचा है कि ऐसी औरतें कितना कष्ट झेलती होंगी! आज इस बात को समझना होगा कि आस्था और धर्म को कानून से ऊपर रखकर जो समाज बनेगा, वह तर्कशील न होकर एक गैर-लोकतांत्रिक समाज ही होगा।

